



सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

सुजस & बुलेटिन

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

जयपुर, बुधवार, 21 अक्टूबर, 2026

एक्सप्रेसवेज पर वाहन चालकों के लिए रियायती दरों पर खाना उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल



पंचायती राज विभाग ने एनएचएआई को श्री अन्नपूर्णा रसोई के खोले जाने के संबंध में लिखा पत्र

एन.एच.ए.आई. इस संबंध में परीक्षण कर पंचायती राज विभाग को भिजवाएगा प्रस्ताव

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के एक्सप्रेसवेज पर दुर्घटनाओं में कमी लाने और वाहन चालकों के लिए आवश्यक सुविधाएं रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रदान किए हैं।

एक्सप्रेसवेज पर स्थित रेस्ट एरियाज़ में श्री अन्नपूर्णा रसोइयों (ग्रामीण) के खोले जाने की संभावना का परीक्षण कर एन.एच.ए.आई. के क्षेत्रीय अधिकारी को प्रस्ताव भिजवाने के लिए पत्र लिखा है।

प्रभावी नियंत्रण के लिए 6-ई आधारित कार्य योजना बनाकर संबंधित विभागों को कार्यवाही के निर्देश दिए।

इसके तहत एजुकेशन, इंजीनियरिंग, एनफोर्समेंट, इमरजेंसी केयर, इवेल्यूएशन, एग्जैमैंट आधारित रणनीति पर निरंतर काम किया जा रहा है।

इसी क्रम में पंचायती राज विभाग ने

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं पर

विश्व बैंक का 'सूत्रा' बदलेगा राजस्थान के शहरों की तस्वीर

राजस्थान के प्रमुख शहरों में सुविधाओं के विस्तार, आधारभूत ढांचे के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और नगर निकायों की वित्तीय एवं प्रशासनिक क्षमता मजबूत करने के उद्देश्य से विश्व बैंक ने सस्टेनेबल अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इन राजस्थान एक्सीलरेटेड (सूत्रा) परियोजना का प्रस्ताव तैयार किया है।

इस प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत 38 करोड़ 57 लाख अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 3 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक है।

विश्व बैंक की ओर से जारी नवीनतम दस्तावेज के अनुसार परियोजना में कुल 32 शहरी स्थानीय

38 करोड़ 57 लाख डॉलर की प्रस्तावित परियोजना से प्रदेश के चार प्रमुख शहरी क्लस्टर का होगा कायाकल्प

निकायों को शामिल किया जाएगा।

इनमें जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर के चार प्रमुख शहरी क्लस्टर तथा उनसे जुड़े 28 सैटेलाइट टाउन शामिल किए जाने प्रस्तावित हैं।

इन क्षेत्रों में वर्ष 2026 में अनुमानित आबादी 78 लाख से अधिक है।

इससे शहरी विकास को अधिक व्यवस्थित बनाने

और नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा।

परियोजना की कार्यान्वयन एजेंसी राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (आरयूआईडीपी) को बनाया जाएगा।

विश्व बैंक में परियोजना की तकनीकी डिजाइन की समीक्षा आगामी 10 दिसम्बर और बोर्ड का अनुमोदन 2 जुलाई 2027 तक होना संभावित है।

इसमें विश्व बैंक के अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक से 27 करोड़ डॉलर का ऋण तथा राज्य सरकार की ओर से 11 करोड़ 57 लाख डॉलर का वित्तपोषण प्रस्तावित है।

पर्यटन, विरासत संरक्षण और शहरी परिवहन को मिलेगा प्रोत्साहन

परियोजना के तहत चारों शहरी क्लस्टर में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण और पुनर्जीवन, शहरी परिवहन एवं कनेक्टिविटी में सुधार, ठोस कचरा प्रबंधन और नागरिक सुविधाओं के विकास से जुड़े कार्य करवाए जाएंगे।

इन प्रयासों का उद्देश्य शहरों को अधिक सुविधाजनक और रहने योग्य बनाना, आवागमन बेहतर करना तथा पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ाना है।

राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहरों और पर्यटन स्थलों को ध्यान में रखते हुए विरासत क्षेत्रों के विकास को भी परियोजना में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

इन शहरों में बढ़ती गर्मी में जल संकट और बारिश के दौरान जलभराव जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए कार्य भी करवाए जाएंगे।

नगर निकायों की आय बढ़ाने और वित्तीय प्रबंधन सुधारने पर बल

विश्व बैंक के दस्तावेज के अनुसार परियोजना के तहत नगर निकायों के राजस्व प्रशासन में सुधार और ऋण प्रबंधन को बेहतर बनाने जैसे उपाय किए जाएंगे।

साथ ही, शहरी स्थानीय निकायों की ऋण लेने की क्षमता मजबूत करने तथा शहरी आधारभूत ढांचे के लिए निजी एवं वाणिज्यिक पूंजी जुटाने की व्यवस्था विकसित करने पर भी जोर रहेगा।

पोषण माह 2026 में राजस्थान का राष्ट्रीय स्तर पर परचम पूरे भारत में हासिल किया द्वितीय स्थान

महिला एवं बाल विकास विभाग के लिए गर्व का क्षण है।

राष्ट्रीय पोषण माह-सितम्बर 2026 के दौरान किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए राजस्थान ने पूरे भारत में द्वितीय स्थान प्राप्त कर इतिहास रचा है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार राजस्थान में 9 सितम्बर से 8 अक्टूबर तक 9वां राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया गया।

प्रदेशभर में आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण संबंधी जनजागरूकता, अन्नप्राशन, गोदभराई, कुपोषित बच्चों का चिन्हीकरण एवं प्रबंधन, पोषण वाटिका, स्वस्थ बालक स्पर्धा जैसे कार्यक्रमों का सघन आयोजन किया गया।

प्रदेश ने निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 113.66% उपलब्धि हासिल की है।

इस उपलब्धि पर उप मुख्यमंत्री तथा महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने समस्त एनएनएम टीम, विभागीय अधिकारियों, जिला एवं ब्लॉक समन्वयकों और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं को हार्दिक बधाई दी है।

साथ ही, उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि हमारी फील्ड की बहनों की दिन-रात की मेहनत, लगन और समर्पण का परिणाम है।

राजस्थान सरकार 'कुपोषण मुक्त राजस्थान, स्वस्थ राजस्थान' के लक्ष्य के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।



इन जिलों के डीडी, सीडीपीओ एलएस तथा जिला समन्वयक, जिला परियोजना सहायक, ब्लॉक समन्वयक एवं समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने असाधारण समर्पण दिखाते हुए पूरे प्रदेश के सामने एक मिसाल पेश की है।

पोषण माह में आयोजित विशेष गतिविधियां

- ▶ आहार विविधता एवं पर्याप्त प्रोटीन
- ▶ आंगनवाड़ी केंद्रों पर ताजा पका हुआ गर्म भोजन
- ▶ सामुदायिक स्वामित्व एवं जवाबदेही
- ▶ बाल्यावस्था विकास के लिए पोषण और प्रारंभिक उद्दीपन
- ▶ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

राजस्थान के टॉप 5 प्रदर्शन करने वाले जिले

जिला	स्थान
जोधपुर	प्रथम
बीकानेर	द्वितीय
पाली	तृतीय
चूरू	चतुर्थ
श्रीगंगानगर	पंचम

विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान: 18-19 वर्ष आयु वर्ग में 4,30,701 आवेदन प्राप्त

2.40 लाख से अधिक पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राजस्थान में पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए संचालित विशेष मतदाता पंजीकरण अभियान के तहत 1 से 20 अक्टूबर 2026 तक कुल 2,40,534 मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि अभियान के तहत विशेष रूप से 18-19 वर्ष आयु वर्ग के युवा एवं प्रथम बार मतदान के लिए

पात्र नागरिकों के पंजीकरण पर फोकस किया जा रहा है।

इस अवधि में युवा एवं जोड़े जाने से शेष रहे अन्य आयु वर्गों में फॉर्म-6 के माध्यम से नाम जुड़वाने के लिए कुल 7,78,147 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

विशेष अभियान के तहत 18-19 वर्ष आयु वर्ग में कुल 4,30,701 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इनमें 1 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त 31,600 अग्रिम आवेदन भी शामिल हैं।

वहीं, 20 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग में 1 से 20 अक्टूबर 2026 तक कुल 3,47,446 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इन आवेदनों में से 3,52,778 आवेदनों के संबंध में 7 दिवस की आपत्ति अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 से 20 अक्टूबर 2026 तक प्राप्त आवेदनों पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) द्वारा सकारात्मक निर्णय के बाद दोनों आयु वर्गों

में कुल 2,40,534 पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़े गए हैं।

इनमें 18-19 वर्ष आयु वर्ग के 58% आवेदनों का निस्तारण कर 1,39,972 तथा 20 वर्ष एवं अधिक आयु वर्ग के 54% आवेदनों का निस्तारण कर 1,00,562 मतदाता शामिल किए गए हैं। शेष आवेदनों के संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

राज्य में अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता

सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।

इसके लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को अभियान की निरंतर निगरानी करने तथा प्राप्त आवेदनों का शीघ्र एवं नियमानुसार निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग के पोर्टल voters.eci.gov.in अथवा ईसीआईएनईटी के माध्यम से ऑनलाइन फॉर्म-6 भरकर मतदाता

सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इस दौरान उन्होंने संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने विधानसभा क्षेत्रों में पात्र युवा एवं नवमतदाताओं के पंजीकरण की गति बढ़ाएं, नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों का प्राथमिकता से निस्तारण सुनिश्चित करें तथा दैनिक प्रगति की नियमित समीक्षा करें।

मतदान के चार चरण

पंच-सरपंच

24, 30 अक्टूबर

5, 16 नवम्बर

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य

22, 28 अक्टूबर

3, 14 नवम्बर

मतगणना

पंच और सरपंच के लिए सुबह 7 बजे से सायं 6 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन मतगणना होगी।

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए सभी चरणों की मतगणना 20 नवम्बर को होगी।

जिला प्रमुख का चुनाव 25 नवम्बर, उप-जिला प्रमुख का 26 नवम्बर, प्रधान का 27 नवम्बर, उप-प्रधान का चुनाव 28 नवम्बर को होगा।

उप-सरपंच का चुनाव मतदान के अगले दिन होगा।

41 जिला परिषद, 457 पंचायत समिति और 14,403 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव करवाए जा रहे हैं, बारं, श्रीगंगानगर, करौली और कोटा जिला परिषद और इनके तहत आने वाली पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसम्बर 2026 में पूरा होगा इसलिए इनका चुनाव कार्यक्रम बाद में घोषित किया जाएगा।

ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्ड पंच के चुनाव मत पेटी तथा जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव ईवीएम से होंगे।

पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026

फलौदी: 9 पंचायत समिति, 305 ग्राम पंचायत

प्रथम चरण			
पंचायत समिति	मतदाता	ग्राम पंचायत	बूथ
फलौदी	71,365	36	81
बाप	95,915	59	119
घटियाली	79,900	44	99
लोहावट	71,160	43	90
देचू	36,834	22	49

प्रथम चरण			
पंचायत समिति	मतदाता	ग्राम पंचायत	बूथ
सेतरावा	34,552	22	50
पीलवा	42,076	26	57
आऊ	45,959	22	55
बापिणी	59,422	31	68



जयपुर: पंचायतीराज आम चुनाव के प्रथम चरण के तहत जिले की आठ पंचायत समितियों एवं जिला परिषद के वार्डों में 22 अक्टूबर को होने वाले मतदान के लिए बुधवार को श्री भवानी निकेतन फार्मसी कॉलेज परिसर से प्रशिक्षण के बाद मतदान दल ईवीएम, बैलेट पेपर एवं निर्वाचन संबंधी आवश्यक सामग्री के साथ उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुए। मतदान दलों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चुनाव सामग्री उपलब्ध कराई गई तथा सामग्री प्राप्त करने के बाद उन्हें संबंधित मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। मतदान दलों की सुविधा के लिए वाहन पार्किंग एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी संदेश नायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मतदान केंद्रों पर मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष, स्वतंत्र, सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।

प्रतापगढ़: 8 पंचायत समिति, 277 ग्राम पंचायत

तृतीय चरण			
पंचायत समिति	मतदाता	ग्राम पंचायत	बूथ
छोटी सादड़ी	92,694	44	123
धमोत्तर	75,284	38	79
धरियावद	1,33,560	53	139
दलोत	59,146	28	68

चतुर्थ चरण			
पंचायत समिति	मतदाता	ग्राम पंचायत	बूथ
प्रतापगढ़	86,232	37	89
अरनोद	46,365	22	58
पीपलखूंट	85,579	36	95
सुहागपुरा	39,008	19	42

HANUMANGARH: HISTORY COMES ALIVE

Formerly the kingdom of Bhati kings, Hanumangarh was originally called Bhatner. However, when Raja Suraj Singh of Bikaner captured the city he rechristened it 'Hanumangarh'. The reason being that the city was won on a Tuesday, a day considered auspicious to the Hindu god Hanuman. The Hanumangarh area is steeped in history and is believed to have once been part of the Indus Valley Civilization. This region was also important due to its location on Delhi-Multan highway as traders from Central Asia, Sindh and Kabul used to travel to Delhi and Agra via Bhatner. Several artefacts, coins and even entire buildings belonging to the era have been found upon excavation in the area.



TEMPLE OF SHRI GOGAJI

At around 120 km from the city of Hanumangarh, lies the Temple of Shri Gogaji.

Legend has it that Gogaji was a warrior who possessed spiritual powers and he is also referred to as the 'God of Snakes'.

The temple was built in his honour almost 900 years ago by Bikaner's Maharaja Shri Ganga Singh and stands on an elevated mount.

What's particularly interesting about the temple is its mix of Muslim and Hindu styles of architecture.

The temple is marked with stunning engravings and houses a beautiful statue of Gogaji on horseback, with a lance in his hand and a snake around his neck.

People of all faiths visit the temple especially during the Gogamedi festival.



KALIBANGAN

A spot that's a must-visit for archaeology buffs, Kalibangan is famous for the site where relics from the Indus Valley Civilization were unearthed.

The relics belong to the Harappan and pre-Harappan settlements from the year 2500 BC.

Excavations at Kalibangan have revealed Harappan seals, human skeletons, unknown scripts, stamps, copper

bangles, beads, coins, toys, terracotta and shells.

Another place to visit here is the Archaeological Museum, which was set up in 1983 to house findings from an excavation conducted on the Harappan site during 1961-1969.

The museum here houses three galleries – the pre-Harappan one, and two devoted to Harappan artefacts

BHATNER FORT



Considered to be one of the oldest forts in India, the Bhatner Fort or Hanumangarh Fort is located on the banks of the river Ghaggar.

The importance of the fort can be gauged from the fact that Emperor Akbar mentioned it in Ain-e-Akbari.

The fort was built around 1700 years ago by Bhupat, the son of Jaisalmer's King Bhatti and has withstood the ravages of time and war extremely well.

Many fearsome rulers including Timur and Prithviraj Chauhan tried to capture the fort, but such was its strength that for centuries no one succeeded at getting their hands on it.

सुजस ई प्रश्नोत्तरी-243

- 1 पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अधिकतम कितने रुपये तक का ऋण रियायती ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है?
(A) ₹1 लाख
(B) ₹2 लाख
(C) ₹3 लाख
(D) ₹5 लाख
- 2 राजस्थान में 'माय भारत' प्लेटफॉर्म पर कितने से अधिक युवा पंजीकृत हैं?
(A) 16 लाख
(B) 20 लाख
(C) 26 लाख
(D) 30 लाख
- 3 एशियन पैरा गेम्स 2026 में महिलाओं की किस श्रेणी की दौड़ में दीप्ति जीवनजी ने स्वर्ण पदक जीता?
(A) टी-12
(B) टी-20
(C) टी-35
(D) टी-47
- 4 'कर्मभूमि से मातृभूमि' अभियान के तहत मुख्य रूप से किस क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है?
(A) ग्रामीण सड़क निर्माण
(B) जल संरक्षण एवं भूजल रिचार्ज
(C) औद्योगिक क्षेत्र विकास
(D) पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण
- 5 राज निवेश पोर्टल पर कितने विभागों की लगभग 190 सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं?
(A) 16 विभाग
(B) 18 विभाग
(C) 20 विभाग
(D) 22 विभाग

सुजस ई प्रश्नोत्तरी-242 के उत्तर: 1-B, 2-B, 3-B, 4-B, 5-C

सही जवाब देने वाले तीन चयनित प्रतिभागी



किशनाराम
जोधपुर



सविता पारीक
जयपुर



रामचन्द्र
नागौर

सही जवाब भेजने वाले 3 विजेताओं की फोटो प्रकाशित कर सम्मान स्वरूप 'राजस्थान सुजस' मासिक पत्रिका नियमित रूप से प्रेषित की जाएगी। इसलिए उत्तर के साथ अपना नाम, पिन कोड सहित पूरा पता, मोबाइल नंबर और फोटो अवश्य भेजें।

dipr.bulletin@gmail.com

सेना कल्याण आवास संगठन की आवासीय परियोजना

मुख्य सचिव ने सेना के अधिकारियों को प्रस्तावित भूखंडों का मौके पर निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्देश



मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में सेना कल्याण आवास संगठन (एडब्ल्यूएचओ) की ओर से निमराना में प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए भूमि आवंटन के संबंध में बैठक आयोजित की गई।

मुख्य सचिव ने कहा कि सेना की ओर से प्राप्त अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

परियोजना के लिए राज्य सरकार की ओर से भूखंडों के विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं। उन्होंने सेना के अधिकारियों को इन भूखंडों का मौके पर निरीक्षण करने तथा उनकी उपयुक्तता का आकलन कर रिपोर्ट एवं सुझाव राज्य सरकार

को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विस्तृत विचार-विमर्श कर भूमि आवंटन के संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

सेना कल्याण आवास संगठन के प्रबंध निदेशक मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) विकल साहनी ने बताया कि निमराना में प्रस्तावित आवासीय परियोजना के लिए संगठन को अब तक 800 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कम से कम 20 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। प्राप्त निर्देशानुसार संगठन की टीम मौके पर जाकर भूखंडों का तकनीकी सर्वेक्षण करेगी।

सेना कल्याण आवास संगठन भारतीय सेना की

पंजीकृत संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई थी।

संगठन का उद्देश्य सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों तथा उनके परिवारों को उपयुक्त स्थानों पर किरायायती दरों पर आवास उपलब्ध कराना है।

संगठन दूरस्थ एवं दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के कारण स्वयं का घर नहीं बना पाने वाले सैनिकों तथा शहीद सैनिकों की विधवाओं को भी आवास सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करता है।

संगठन स्व-वित्तपोषित संस्था के रूप में 'नो प्रॉफिट, नो लॉस' के सिद्धांत पर कार्य करता है। संगठन द्वारा देशभर में अब तक 36 हजार आवासीय इकाइयों की बिक्री की जा चुकी है।



महानिदेशक, आईजीपीआरएस, नीरज के. पवन ने बुधवार को राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली, प्राप्त शिकायतों के निस्तारण तथा राजस्थान संपर्क एआई के माध्यम से शिकायतों के विश्लेषण की प्रक्रिया की जानकारी ली।